



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08092021-229488
CG-DL-W-08092021-229488

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32]	नई दिल्ली, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2021 शनिवार/ भाद्र 7—भाद्र 13, 1943
No. 32]	NEW DELHI, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2021, SATURDAY/BHADRA 7—BHADRA 13, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विदेश मंत्रालय
(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

का.आ. 597.—राजनयिक और कौंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद् द्वारा, केंद्र सरकार भारत के दूतावास, रियाद में श्री ईश्वर सिंह डबास, सहायक अनुभाग अधिकारी, को दिनांक 25 अगस्त 2021 से सहायक कौंसुलर अधिकारी के तौर पर कौंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2016]

ब्रह्म कुमार, निदेशक (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV DIVISION)

New Delhi, the 25th August, 2021

S.O. 597.—In pursuance of clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Ishwar Singh Dabas, Assistant Section Officer in the Embassy of India, Riyadh as Assistant Consular Officer to perform Consular services with effect from 25 August, 2021.

[F. No. T-4330/01/2016]

BRAMHA KUMAR, Director (CPV)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 598.—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऐसी सभी शक्तियों या कर्तव्यों या उनमें से कोई, जिसका उक्त सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की ऐसी धाराओं के अधीन, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रयोग और निर्वहन किया जा सके, ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं;

परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा जबकि उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन ऐसी परिस्थिति में और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, किया जाएगा, जो नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट और निदेशित की जाए।

अनुसूची

क्रम सं.	अधिनियम की धारा	संक्षिप्त में कर्तव्यभार का स्वरूप	उन व्यक्तियों का पदनाम और प्राधिकृत पता जिन्हें शक्ति प्रत्यायोजित की गई है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14(1)	प्रतिकर के अवधारण की पद्धति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
2.	14(4)	प्रतिकर के संबंध में अधिकरण के समक्ष कथन	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
3.	16	अधिकरण के अधिनिर्णय पर ब्याज पर संदाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

4.	17	प्रतिकर का संदाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)
5.	21	सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय : 6/42, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

[फा. सं. 43015/20/2015-एलए एण्ड आईआर/खंड-I]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 3rd September, 2021

S.O. 598.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby directs that all the powers and duties that may be exercised or discharged by the said Government under the sections of the Act as are specified in column (2) of the Schedule annexed hereto shall be exercised and discharged by the person specified against in the corresponding entry in column (4) of the said Schedule:

Provided that the exercise and discharge of powers and duties under sub-section (1) of section 14 of said Act shall be subject to the prior approval of the Central Government, whereas the exercise and discharge of powers and duties under section 21 of the said Act by the officers as specified in the said Schedule shall be in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified and directed by an order, with the prior approval of the Central Government, in writing, by the Chief Executive Officer, Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).

SCHEDULE

Serial Number	Section of the Act.	Nature of assignment in brief	Designation and official address of the person to whom power delegated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	14(1)	Method of determining compensation	Chief Executive Officer	Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
2.	14(4)	Statement before the Tribunal regarding compensation.	Chief Executive Officer	Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
3.	16	Payment of interest on award of the Tribunal.	Chief Executive Officer	Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).

4.	17	Payment of compensation.	Chief Executive Officer	Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
5.	21	Power to obtain information.	Chief Executive Officer	Neyveli Uttar Pradesh Power Limited, Registered Office: 6/42, Vipul Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).

[F. No. 43015/20/2015-LA&IR/Vol. I]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 599.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 6 अगस्त, 1994 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1857, तारीख 24 जून, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

अधिकारी का पदनाम		सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
(1)		(2)
“59.	उप-क्षेत्रीय प्रबंधक/अभिकर्ता, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, छत्तरपुर उप-क्षेत्र, पाथाखेड़ा क्षेत्र, पोस्ट- पाथाखेड़ा, जिला बैतूल- 460449 मध्य प्रदेश ।	छत्तरपुर कोयला खान (छत्तरपुर-I, छत्तरपुर II खान) के सभी स्थान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के या उनके नियंत्रणाधीन अन्य स्थान ।
60.	उप-क्षेत्रीय प्रबंधक/अभिकर्ता, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तवा उप-क्षेत्र, पाथाखेड़ा क्षेत्र, पोस्ट- पाथाखेड़ा, जिला बैतूल- 460449 मध्य प्रदेश ।	तवा कोयला खान के सभी स्थान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के या उनके नियंत्रणाधीन अन्य स्थान ।
61.	उप-क्षेत्रीय प्रबंधक/अभिकर्ता, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तवा- II, उप-क्षेत्र, पाथाखेड़ा क्षेत्र, पोस्ट- पाथाखेड़ा, जिला बैतूल- 460449 मध्य प्रदेश ।	तवा कोयला खान के सभी स्थान और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के या उनके नियंत्रणाधीन अन्य स्थान ।”

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1857, तारीख 24 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :

- (i) अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1419, तारीख 10 जून, 2004 में प्रकाशित की गई थी ।
- (ii) अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1280, तारीख 27 अप्रैल, 2007 में प्रकाशित की गई थी ।
- (iii) अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1386, तारीख 12 जून, 2008 में प्रकाशित की गई थी ।
- (iv) अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 937, तारीख 12 जून, 2018 में प्रकाशित की गई थी ।

[फा. सं. 43022/5/2018-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

New Delhi, the 3rd September, 2021

S.O. 599.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th August, 1994, *vide* number S.O. 1857, dated the 24th June, 1994, namely:-

2. In the said notification, in the Table, after serial number 58 and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely :-

TABLE

Designation of the Officer		Categories of public premises
(1)		(2)
“ 59.	Sub-Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited Chhatarpur Sub-Area, Pathakhara Area, Post Office- Pathakhara District- Betul, 460449 Madhya Pradesh.	All premises of Chhatarpur Coal Mines (Chhatarpur- I and Chhatarpur-II Mines) and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
60.	Sub-Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited Tawa Sub-Area, Pathakhara Area, Post Office- Pathakhara District- Betul, 460449 Madhya Pradesh.	All premises of Tawa Coal Mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.
61.	Sub-Area Manager/Agent, Western Coalfields Limited Tawa- II Sub-Area, Pathakhara Area, Post Office- Pathakhara District- Betul, 460449 Madhya Pradesh.	All premises of Tawa-II Coal Mines and other premises belonging to or under the control of the Western Coalfields Limited, Nagpur.”

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1857, dated the 24th June, 1994 and was subsequently amended *vide* notifications:

- (i) The notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1419, dated the 10th June, 2004.
- (ii) The notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1280, dated the 27th April, 2007.
- (iii) The notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1386, dated the 12th June, 2008.
- (iv) The notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 937, dated the 12th June, 2018.

[F. No. 43022/05/2018-LA& IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 600.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मेसर्स अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता; महाप्रबंधक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, झुंझुनू (राजस्थान); मुख्य प्रबंधक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, झुंझुनू (राजस्थान) के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और श्री कैलाश चंद, कार्यकर्ता के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 1/2020) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 31.08.2021 को प्राप्त हुआ था।

[सं. जेड-16025/4/2021-आईआर-(एम)]

डी. गुहा, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 600.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1/2020) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. The Chairman-Cum-Managing Director, Hindustan Copper Limited, Kolkata; The General Manager, Hindustan Copper Limited, Jhunjhunu (Rajasthan); The Chief Manager, Hindustan Copper Limited, Jhunjhunu (Rajasthan) and Shri Kailash Chand, Worker which was received by the Central Government on 31.08.2021.

[No. Z-16025/4/2021-IR (M)]

D. GUHA, Under Secy.

अनुबंध**केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर सी.जी.आई.टी. प्रकरण सं. 1/2020**

पीठासीन अधिकारी : राधामोहन चतुर्वेदी
 श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री बिरदू राम
 निवासी—मुकाम पोस्ट मानोता कलां,
 ग्राम मानोता खुर्द, पोस्ट खेतड़ी नगर,
 तहसील खेतड़ी, जिला—झुंझुनू, राजस्थान

बनाम

1. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड जरिये
 चेयरमेन—कम—मैनेजिंग डायरेक्टर,
 ताम्र भवन—1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता
2. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड जरिये
 जनरल मैनेजर, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स,
 खेतड़ी नगर, जिला—झुंझुनू, राजस्थान—333504
3. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड जरिये
 मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन)
 खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर,
 जिला—झुंझुनू, राजस्थान— 333504

प्रार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत —अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर से : श्री अशोक वर्मा —अधिवक्ता

: अधिनिर्णय :

दिनांक : 08.07.2021

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 6947/2019 कैलाश चंद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दि. 10.12.2019 को पारित निर्णय/आदेश के अनुसरण में प्रार्थी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे मात्र अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 2—ए के प्रावधानों के अन्तर्गत यह दावे का अभिकथन दिनांक 10.1.2020 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का कथन है कि वह विपक्षी संस्थान 1 के अधीन दिनांक 18.10.2011 को लोडर कम लोको सहायक (ट्रेनी) के पद पर भर्ती हुआ। प्रार्थी को इंडक्शन ट्रेनी कार्यक्रम में दिनांक 20.10.2011 से 30.10.11 तक भेजा गया। प्रार्थी ने 31.10.2011 को ड्यूटी ज्वाइन की। दिनांक 13.3.2013 को विपक्षी ने एक कारण बताओ नोटिस प्रार्थी को दिया। जिसका प्रतिउत्तर प्रार्थी ने प्रस्तुत किया। एक और कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.4.2013 को प्रार्थी को दिया गया। जिसका प्रतिउत्तर भी प्रार्थी ने देते हुये ऑरोप का खंडन किया। किन्तु विपक्षीगण ने बिना नियमित जांच किये प्रार्थी को सेवामुक्त कर दिया। प्रार्थी ने इस सेवामुक्ति के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पीटीशन 7263/2013 में दिनांक 1.8.2014 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थी के सेवामुक्ति आदेश दिनांक 23.4.2013 को अवैध घोषित कर दिया। इस आदेश को विपक्षीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई। जिस पर दिनांक 31.5.2016 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच करते हुये आदेश पारित किया जावे। प्रार्थी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने नियुक्ति आवेदन में गलत जानकारी दी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2010 जो ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा जारी किया गया था, उसमें विसंगति पाई गई। एक प्रमाण पत्र में दिनांक 15.11.2007 से 20.11.2010 तक कार्यानुभव दर्शाया गया और दूसरे प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2010 में ही, कार्य की अवधि 6.7.2009 से 15.10.2010 दर्शायी गयी। प्रार्थी ने इस आरोप का विस्तृत जवाब दिनांक 6.10.2018 को प्रस्तुत किया और साथ ही भविष्य निधि अंशदान का भी विवरण प्रस्तुत कर दिया। किन्तु विपक्षीगण ने दिनांक 29.10.2018 को एक आदेश जारी कर पूर्व में पारित सेवामुक्ति आदेश दिनांक 23.4.2013 को यथावत रखा। प्रार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु उस पर भी कोई विचार नहीं किया इसलिये प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 6947/2019 प्रस्तुत की। जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.2019 को यह आदेश दिया कि प्रार्थी श्रम न्यायालय के समक्ष अपना विवाद प्रस्तुत करें।

3. प्रार्थी पर लगाये गये आरोप निराधार है। विपक्षीगण ने सेवामुक्ति के पूर्व कोई नियमित घरेलू जांच नहीं की और प्रार्थी के जवाब पर कोई विचार नहीं किया। प्रार्थी को उसके बचाव का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिये सेवामुक्ति का जो दण्ड दिया गया है वह अवैध है। प्रार्थी दिनांक 23.4.2013 से बेरोजगार है। अतः विपक्षीगण द्वारा

दिनांक 29.10.2018 को की गई सेवामुक्ति आदेश को अवैध घोषित करते हुये प्रार्थी को दिनांक 23.4.2013 से सेवा में निरन्तर मानते हुये सभी परिलाभ दिलवाये जावें और बहाल किया जावें।

4. विपक्षीगण ने प्रार्थी के दावे के कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कहा है कि प्रार्थी के प्रशिक्षु काल में प्रार्थी ने आवेदन के साथ कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये और गलत जानकारी दी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगे गये जो संतोषजनक नहीं थे। इसलिये सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफर लेटर की शर्तों के अनुसार प्रार्थी को तत्काल सेवामुक्त कर दिया गया। विपक्षीगण का यह कथन है कि दिनांक 6.10.2018 को प्रार्थी ने कारण बताओ नोटिस का जो प्रतिउत्तर दिया उसमें कोई नया तथ्य नहीं था। इसमें प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि मैसर्स ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के ठेके में वह दिनांक 6.7.2009 से 15.9.2010 तक ही कार्यरत था जबकि अनुभव प्रमाण पत्र जो आवेदन के साथ प्रस्तुत किया था उसमें कार्य की अवधि 15.11.2007 से 20.11.2010 तक दर्शायी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कार्यानुभव प्रमाण पत्र में कांट-छांट और छेड़छाड़ की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेशानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच हेतु कारण बताओ नोटिस प्रार्थी को दिया गया था और उसका स्पष्टीकरण भी लिया गया। इस प्रकार दो बार की गई जांच के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा प्रमाण पत्र में कांटछाट किया जाना प्रमाणित हुआ, और सेवामुक्ति बरकरार रखी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी दस्तावेजों की दुबारा विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया था और यह भी कहा था कि जिन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं इन व्यक्तियों को सेवा में रखने के लिये प्रबंधन बाध्य नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध दस्तावेजों की मात्र विस्तृत जांच ही की जानी थी अन्य कोई नियमित जांच का निर्देश नहीं था। अतः वाद निरस्त किया जावें।

5. प्रार्थी ने अपने साक्ष्य में स्वयं प्रार्थी कैलाश चन्द्र को परीक्षित किया। प्रलेखित साक्ष्य में प्रदर्श-डब्ल्यू 1 से 3 (जो कि एकाधिक पृष्ठों में हैं) प्रदर्शित किये।

6. विपक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श-एम 1 मुकेश कुमार कनिष्ठ प्रबंधक को परीक्षित किया और प्रलेखित साक्ष्य में प्रदर्श-एम 1 से 22 तक प्रलेख प्रदर्शित किये।

7. दिनांक 13.4.2021 को मैंने उभयपक्ष के तर्क वितर्क इस विवाद के सम्बन्ध में सुने तथ उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

8. अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा जो कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये, उनके संबंध में प्रार्थी के विरुद्ध कोई विधिवत घरेलू जांच नहीं की गई, और उसे प्रतिरक्षा का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। प्रार्थी ने विपक्षीगण के अधीन दिनांक 15.11.2007 से 1.12.2010 तक विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्य किया था। आवेदन प्रस्तुत करते समय ये सभी ठेकेदार उपलब्ध नहीं थे। चूंकि मैसर्स ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के प्रतिनिधि श्री ज्ञानचन्द सैनी उन ठेकेदारों के कार्य भी देखते थे इसलिये उनका अनुभव प्रमाण पत्र ले लिया। बादमें विपक्षीगण के कहने पर प्रार्थी ने ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के समय का दूसरा प्रमाण पत्र लेकर दे दिया। प्रार्थी ने कोई कूटरचना नहीं की। यदि कूटरचना का आरोप प्रार्थी पर लगाया गया था तो उसकी विधिवत घरेलू जांच किया जाना आवश्यक था। मात्र कारण बताओ नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं था। प्रार्थी ने दिनांक 15.11.2007 से 30.11.2010 तक विभिन्न ठेकेदारों के अधीन जो कि विपक्षीगण की खदान में कार्यरत थे। कार्य का अनुभव प्राप्त करना प्रमाणित किया है, और भविष्य निधि के अंशदान संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं। इसलिये विपक्षीगण द्वारा दिनांक 23.4.2013 को की गई सेवामुक्ति को 29.10.2018 को यथावत रखते हुये प्रार्थी को सेवामुक्त करना अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-

1. ए.आई.आर. सुप्रीम कोर्ट 1080 वी.पी. आहूजा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य

2. सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील सं. 777/2020 डॉ. विजयकुमारन सी.पी.वी./सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल व अन्य

9. विपक्षीगण की ओर से यह कहा गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय दिनांक 31.5.2016 में पारित निर्देश की पूर्ण अनुपालना विपक्षीगण ने की है। दिनांक 4.10.2018 को दस्तावेजों की विस्तृत जांच करते समय प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके प्रतिउत्तर में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर यथोचित विचार भी किया गया। तत्पश्चात जब अनुभव प्रमाण पत्र में कांटछाट या छेड़छाड़ किया जाना प्रमाणित पाया गया तो विपक्षीगण के सेवा नियमों के अनुरूप प्रार्थी को सेवा में रखा जाना उचित नहीं पाया गया, और सेवामुक्त कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को यह उन्मुक्ति दी गई है कि वह उन व्यक्तियों के मामले को पृथक से विचारित करें, जिन्होंने प्रमाण पत्रों में कांटछाट की है। विपक्षीगण को यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित श्रमिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उस पर विनिश्चय करें। यदि संबंधित प्रार्थी कांटछाट के आरोप को स्पष्टीकृत करने में विफल रहे, तो ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करने से विपक्षीगण को विरत रहने की छूट दी गई है। इस प्रकरण में प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 31.10.2011 को (प्रशिक्षण में) ड्यूटी जॉइन की। इस प्रकार दिनांक 23.4.2013 तक प्रार्थी द्वारा 18 माह का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया था। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही प्रार्थी को 6 माह की परिवीक्षा के अधीन रखा जाना था। यह परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर प्रार्थी/श्रमिक को नियुक्ति दी जानी थी। चूंकि प्रार्थी 23.4.2013 को नियमित रूप से नियुक्त ही नहीं था, उसकी स्थिति एक प्रशिक्षु अथवा परिवीक्षाधीन श्रमिक की थी जिसके विरुद्ध नियुक्ति प्रस्ताव अथवा चयन पत्र की शर्तों के अनुरूप सेवासमाप्ति के पूर्व कोई घरेलू जांच किया जाना अपेक्षित नहीं था। इसलिये प्रार्थी की सेवामुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में विधिवत की गई है।

10. उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है :-
2017 (4) WLC - 186 प्रवीण कुमार जैन बनाम द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रस्तुत किया।
11. मैंने उभयपक्ष के तर्कों, साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टान्तों में पारित विधि पर मनन किया।
12. उभयपक्ष के तर्कों व साक्ष्य पर मनन के उपरांत इस विवाद में निम्नांकित विचारणीय बिंदु उत्पन्न हुए हैं :-
 1. क्या प्रार्थी की सेवामुक्ति दिनांक 23.4.2013 के पूर्व विपक्षी द्वारा सम्यक घरेलू जांच किया जाना आवश्यक था एवं घरेलू जांच प्रक्रिया के अनुसरण के बिना प्रार्थी की सेवामुक्ति प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है ?
 2. अनुतोष ?
13. **विचारणीय बिंदु सं. 1 :-**
तथ्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति न करते हुए मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश दिनांक 31.5.2016 में पारित दिशा-निर्देशों व निष्कर्षों का उल्लेख करना सुसंगत समझता हूँ।
 1. यदि एक अभ्यर्थी वांछित कार्यानुभव नहीं रखता है तो वह नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है।
 2. माननीय एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए माननीय खंडपीठ ने विपक्षी कंपनी को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक अभ्यर्थी का मामला पृथक से विचारित करें।
14. विपक्षी (कंपनी) को यह उन्मुक्ति प्रदान की गई है कि प्रत्येक अभ्यर्थी (प्रार्थी) के मामले पर विचार करते समय उन अभ्यर्थियों को छोड़ दे जिन्होंने प्रमाणपत्रों में हेरा-फेरी (manipulation) की है। ऐसा विनिश्चय सम्यक खोजबीन के उपरांत समुचित रीति से लिया जावे क्योंकि पूर्व में अभ्यर्थियों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस में प्रमाणपत्रों में हेराफेरी का अभियोग नहीं लिखा गया था। कंपनी के लिए यह समुचित होगा कि वह संबंधित याची (प्रार्थी) का स्पष्टीकरण आहूत करें - तथा यदि वह हेराफेरी के अभियोग को स्पष्ट करने में विफल रहे, तो कंपनी ऐसे प्रार्थी के मामले पर विचार करने से विरत रहने को उन्मुक्त होगी।
15. उल्लेखनीय है कि मान. खंडपीठ द्वारा प्रार्थी के मामले पर खोजबीन परक तथ्यान्वेषण करने व पुनः कारण बताओ नोटिस जारी करने मात्र का निर्देश दिया है, किसी औपचारिक घरेलू जांच किये जाने का निर्देश नहीं।
16. इस संदर्भ में प्रार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि एक अस्थाई/परिवीक्षाधीन श्रमिक को भी सेवामुक्ति के पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अन्तर्गत नियमित जांच व सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित है।
17. इस तर्क में समर्थन में उन्होंने वी.पी. आहूजा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अधिमत का अवलंब लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में एक अस्थाई या परिवीक्षाधीन श्रमिक को लांछन के आधार पर सेवासमाप्ति के पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का संरक्षण देय होना अधिनिर्णीत किया है - तथा जांच कार्यवाही को आवश्यक बताया है।
18. इसी क्रम में डॉ. विजयकुमारन सी.पी.वी./सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अधिमत का आधार लिया है। इस निर्णय में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी को भी लांछनात्मक/दंडात्मक आधार पर सेवामुक्ति किया जाने के पूर्व उस पर लगाये गये आरोप की पूर्ण औपचारिक जांच प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है।
19. विपक्षी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय प्रवीण कुमार जैन बनाम द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में पारित अधिमत का अवलंब लिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह अधिमत व्यक्त किया है कि जहां नियुक्ति मिथ्या सूचना एवं प्रमाणपत्र पर आधारित हो, अभ्यर्थी (कर्मचारी) परिवीक्षा पर हो, तो वह स्थाई कार्मिक के समान अधिकार प्राप्त नहीं होता- नियमित जांच किया जाना आवश्यक नहीं है।
20. इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016 (7) स्केल 378 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एम. मास्करन 1995 सप्ली.(4) एस.सी.सी. 100 एवं आर विश्वनाथ पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरल (2004) 5 एस.सी.सी. 105 में पारित विधि को आधार बनाया है जिसमें कहा गया है कि छल व मिथ्याख्यापन के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई हो तो प्राप्तकर्ता श्रमिक की सेवामुक्ति के पूर्व जांच की आवश्यकता नहीं है।
21. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधिक दृष्टान्तों के प्रकाश में प्रार्थी से संबंधित तथ्यात्मक परिदृश्य का परीक्षण आवश्यक है।
22. प्रार्थी स्वयं का यह अभिवचन है कि प्रदर्श एम-7 (चयनपत्र) दिनांक 18.10.2011 द्वारा उसे चयनित किया तथा कार्यग्रहण तिथि 31.10.2011 से 18 माह के लिए उसे प्रशिक्षणाधीन रहना था। प्रशिक्षण अवधि 18 माह की समाप्ति पर नियमित वेतनमान में 6 माह की अवधि के लिए प्रार्थी को परिवीक्षाधीन रखा जाना था। इसी चयनपत्र प्रदर्श एम-7 में यह शर्त स्पष्ट रूप से अंकित की गई है कि यदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है तो बिना किसी सूचना या कारण बताये प्रशिक्षण/सेवा से उसे हटा दिया जावेगा।

23. इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की प्रशिक्षण अवधि 31.10.11 से (18 माह तक अर्थात्) 30.4.13 तक नियत थी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर ही प्रार्थी को परिवीक्षाधीन रखा जाना था। किंतु 30.4.13 के पूर्व ही 23.4.13 को प्रार्थी को सेवामुक्त कर दिया गया। 23.4.13 को प्रार्थी की प्रस्थिति न तो स्थाई/अस्थायी श्रमिक की थी न ही परिवीक्षाधीन श्रमिक की वरन वह प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षु मात्र था।

24. प्रार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अर्थात् नियुक्त किये जाने के पूर्व ही दि. 11.4.13 को नोटिस दिया गया जिसमें प्रार्थी को 6 माह का लोको ट्रेनिंग ऑपरेशन ऑफ लोडर का कार्यानुभव न होना दर्शाया गया। प्रार्थी पर यह भी आक्षेप किया गया कि उसने मै. ज्ञानी इलेक्ट्रीकल्स से फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र बनवाकर कंपनी में नियुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ छेड़छाड़ भी की है। प्रार्थी ने यद्यपि इस नोटिस के प्रत्युत्तर में अनुभव प्रमाणपत्रों से छेड़छाड़ करने का तथ्य अस्वीकार किया है। किंतु ए.ड.1 कैलाशचंद्र ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रदर्श एम-3 प्रमाणपत्र उसने इस कारण दिया कि वह अपनी योग्यता और अनुभव प्रमाणित कर सकें। प्रार्थी कहता है कि उसने ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के अधीन 30.11.10 तक कार्य किया था तथा प्रदर्श एम-5 प्राप्त कर लिया था।

25. इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रदर्श एम-3 व ए. 5 दोनों ही अनुभव प्रमाणपत्रों को कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करना एक स्वीकृत तथ्य है।

26. उल्लेखनीय यह है कि प्रदर्श एम-5 व प्रदर्श एम-3 प्रमाणपत्र दोनों ही ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा दि. 30.11.2010 को संदर्भ सं. 77 के माध्यम से जारी किये गये हैं। प्रदर्श एम-3 में कार्य की अवधि 15 नवंबर 2007 से 30.11.2010 दर्शाई गई है, जबकि प्रदर्श एम-5 में यह अवधि 6.7.2009 से 15.10.2010 ही दर्शाई गई है। साक्ष्य में प्रार्थी ने ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के अधीन मात्र 15.10.10 तक ही कार्य करना स्वीकार किया है जिसका प्रमाणपत्र प्रदर्श एम-5 है—किंतु साथ ही प्रार्थी इसी ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स का प्रमाणपत्र प्रदर्श एम-3 भी प्रस्तुत करना स्वीकार करता है—जिसमें कार्यानुभव 15.11.2007 से 30.11.2010 होना अंकित है जबकि प्रार्थी ने 15.11.2007 से तथा दि. 30.11.2010 तक ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स के अधीन वास्तव में कार्य ही नहीं किया है। दोनों ही प्रमाणपत्र एक ही संदर्भ संख्या 77 से दि. 30.11.2010 को जारी हुए हैं जिनमें से एक प्रमाणपत्र निश्चित रूप से मिथ्या तथ्यों का निरूपण करता है। प्रार्थी के अनुसार उसने विभिन्न पैट्टी टेकेदारों के अधीन कार्य किया था जिनको वह नहीं जानता था—इसलिए ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स से ही प्रमाणपत्र ले लिया था। इस प्रकार प्रदर्श एम-3 प्रमाणपत्र प्रार्थी द्वारा अपना कार्यानुभव विज्ञप्ति के अनुरूप प्रमाणित करने लिए ज्ञानी इलेक्ट्रिकल्स से बनवाया जाना प्रमाणित होता है—जबकि प्रार्थी ने प्रमाणपत्र में वर्णित अवधि के अनुरूप कार्य नहीं किया था।

27. इस तथ्यात्मक परिदृश्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निर्णयों में प्रतिपादित विधि सेवा में नियुक्त या परिवीक्षाधीन कार्मिकों पर लाञ्छनात्मक आरोप के आधार पर सेवामुक्ति के संबंध में प्रतिपादित की गई है—जबकि हस्तगत विवाद में प्रार्थी मात्र चयनित प्रशिक्षु होना प्रमाणित हुआ है—जिसका प्रशिक्षण भी पूर्ण नहीं हुआ, न ही परिवीक्षाकाल प्रारंभ हुआ। इसलिए तथ्यात्मक भिन्नता के कारण यह विधि प्रार्थी के पक्ष में सहायक नहीं है। प्रार्थी को कंपनी (विपक्षी) द्वारा इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है कि उसने नियुक्ति प्राप्त करने हेतु ऐसे मिथ्या कार्यानुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जो वास्तविक व सत्य नहीं थे—इसलिए प्रार्थी की सेवासमाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की औपचारिक जांच प्रक्रिया को अपनाकर सुनवाई का अवसर देना विधितः अपेक्षित नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवीण कुमार जैन बनाम द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्णय में पारित विधि इस प्रकरण के तथ्यों से सुसंगत एवं प्रभावी प्रकट होती है।

28. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दि. 31.5.2016 में भी किसी प्रकार की औपचारिक जांच प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्देश न देते हुए मात्र खोजबीन परक प्रलेखों का परीक्षण एवं प्रार्थी का मात्र स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है—जिसका सम्यक अनुपालन विपक्षी द्वारा किया जाना प्रमाणित होता है। इस निष्कर्ष के उपरांत दिनांक 23.4.13 को विपक्षी द्वारा की गई प्रार्थी की सेवामुक्ति वैध प्रमाणित होती है। अतः यह विचारणीय बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

29. विचारणीय बिंदु सं. 2

विचारणीय बिंदु सं. 1 पर पारित विवेचित निष्कर्ष के प्रकाश में प्रार्थी की सेवासमाप्ति चूंकि वैध प्रमाणित हुई है—इसलिए प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

30. इस औद्योगिक विवाद का न्यायनिर्णय इसी प्रकार किया जाता है। अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जावे।

राधा मोहन चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 601.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र, संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 2, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ सं. 80/2009) को प्रकाशित करती है।

[सं. एल-31011/4/2009-आईआर (बी-II)]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 31st August, 2021

S.O. 601.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 80/2009) of the Cent.Govt.Indus.Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Mumbai Port Trust and their workmen.

[No. L-31011/4/2009-IR (B-II)]

RAJENDER SINGH, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT : S. S. GARG, Presiding Officer/Link Officer

REFERENCE NO.CGIT-2/ 80 of 2009

EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF MUMBAI PORT TRUST

The Chairman,
Mumbai Port Trust,
Shoorji Vallabhadas Marg,
Ballard Estate, Mumbai,
MUMBAI – 400 001.

AND

THEIR WORKMEN

The General Secretary,
Mumbai Port Trust General Workers Union,
1st Floor, Kavarana Building, 26/4, P.D. Mello Road,
Wadi Bunder, Mumbai.
MUMBAI – 400 009.

APPEARANCES:

FOR THE EMPLOYER : Mr. Umesh Nabar Advocate

FOR THE WORKMEN : Mrs. P. Shetty Advocate

Mumbai, dated the 23rd July, 2021

AWARD PART – II

1. This is reference made by the Central Government in exercise of powers under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide Government of India, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide its order No. L-31011/4/2009 – IR (B-II) dated 13.10.2009. The terms of reference given in the schedule are as follows :

“Whether the action of the management of Mumbai Port Trust by compulsory retiring the workman Shri Jaywant Govind Raut, Mazdoor, Telephone Section, P & R Department of the Mumbai Port Trust w.e.f. 19.3.2008 is legal and justified ? What relief the workman is entitled to ?”

2. After the receipt of the reference, both the parties were served with the notices. They appeared through their respective representatives.
3. The second party union has filed statement of claim Ex.5. According to the second party union, the concerned workman was appointed as Mazdoor in Docks dept on and from 16.11.1981. He was posted on re-employment as Mazdoor in Telephone Section of Planning & Research Dept. w.e.f. 20.7.2001. He was in continuous employment of the first party management from 16.11.81 and a permanent Gr.D employee.
4. It is the case of the second party union that the concerned workman was compulsorily retired from the services w.e.f. 19.3.08 illegally. He was issued charge sheet dt. 5.1.07 on the allegations that he was indulged in harassing one of the lady officers of MbPT. The concerned workman submitted his reply to the charge sheet. The first party thereafter instituted the departmental enquiry to investigate into the charges. The departmental enquiry was commenced on 12.4.07 and concluded on 23.10.07. The E.O. by report dt. 12.11.07 held all the charges leveled against the workman as proved. Thereafter the disciplinary authority concurred with the findings of the E.O. and workman was issued show cause notice dt. 3.1.08. The workman submitted his explanation on 28.1.08. The penalty of removal from service was imposed upon the concerned workman by order dt. 19.3.08. Being aggrieved by the order of the disciplinary authority imposing punishment of removal, concerned workman preferred appeal dt. 3.4.08 before the appellate authority. The appellate authority granted personal hearing to the concerned workman on 21.5.08. The appellate authority modified the penalty of removal from service to compulsory retirement by order dt. 30.5.08.
5. It is the case of the concerned workman that in the departmental enquiry prosecution could not adduce any evidence against him which warranted his compulsory retirement from service. E.O. did not appreciate voluminous evidence adduced on behalf of the workman.
6. It is also a case of the concerned workman that he himself and his wife were assaulted and threatened on 26.12.05 and 31.12.05 on the incidence of one Mrs. P.R. Patne and therefore he and his wife lodged complaint with the concerned authorities. Thereafter Mrs. Patne has lodged complain on 5.8.06. However, no action has been taken by the authority even after follow up letters by the union on behalf of the workman & his wife and instead action has been taken against the workmen. As such the enquiry was carried out hurriedly by the E.O.
7. It is then case of the concerned workman that on one hand he was compulsory retired on 19.3.08 and on the other hand he was issued with 2nd charge sheet vide letter dt. 18.9.08. He sought time to file reply. The management in reply to said representation dt. 3.10.08 considered and agreed to give extension to file reply by another 30 days. The second charge sheet is still pending and the management has not cancelled or withdrawn the said second charge sheet.
8. It is then case of the concerned workman that Mrs. Patne also lodged another two private complaints on the same matter before Metropolitan Magistrate Court which is pending. The management without waiting for the outcome of the criminal proceedings hurriedly conducted the enquiry and made the workman to retire compulsorily. As such the action taken by the management in terminating i.e. compulsorily retiring the workman from service is illegal.
9. Union therefore by its letter dt. 6.11.08 raised the industrial dispute before the ALC Mumbai. ALC Mumbai admitted the said dispute. However, conciliation proceedings ended in failure. Conciliation report was sent by ALC. As such the dispute is referred for adjudication of the tribunal. The union is therefore asking to held and declare that the action of the management of compulsorily retiring the concerned workman w.e.f. 19.3.08 is illegal and that the concerned workman is entitled for reinstatement in his service with full back wages and continuity of service.
10. The first party management resisted claim by filing written statement Ex.6 contending therein that the concerned workman was arrested and detained by the police authority from 26.1.06 to 2.2.06 u/s. 506 (2), 507 & 509 of IPC for alleged involvement in the case of sexual harassment of Mrs. Patne, Asst. Railway Manager of first party. As the workman was in police custody for the period exceeding 48 hours, he was placed under suspension w.e.f. 27.1.06 by order dt. 21.2.06. Thereafter the suspension of the workman was withdrawn on and from 14.8.06 pending departmental enquiry on the basis of recommendation of review committee dt. 8.8.06 and he was allowed to resume duties. Taking into consideration his involvement in case of sexual harassment of the lady employee of the first party and his consequent detention in police custody which amounts to misconduct under MbPT Conduct Regulations 1976, he was issued the charge sheet for violations of Regulations 3 (1), 3 (1a) (vii) & (xv) & 3 (7) of said Regulations. His reply was not found satisfactory and hence enquiry was conducted. There were 28 hearings in the departmental enquiry so as to give ample opportunity to the workmen to defend his case. Opportunities were availed by the concerned workman. As such the sufficient opportunity to defend himself was given to the concerned workman.

11. It is then case of the first party management that during the pendency of disciplinary action against the workman resulting into compulsory retirement upon him once again Sr. Inspector of Police MRA Marg Police station informed the first party that workman was arrested on 29.6.07 for the offence u/s. 193, 465, 467, 469 read with section 120 (b), 34 & 109 of IPC and remanded to police custody till 6.7.07. He was placed under suspension and continued to remain under suspension till 19.4.08 i.e. the date on which disciplinary authority passed an order imposing punishment of removal from service upon the workman on the recommendations of the review committee. On the basis of detention of workman in the police custody the disciplinary action was taken against him and therefore the second charge sheet was issued before the order of disciplinary authority imposing the punishment of removal from services. The first party accepted the request of the concerned workman and Marathi translation of the charge sheet was given to him. Copy of report of the police officer was also forwarded to him. So according to the first party it is not necessary for the first party to deal with contention of second party in respect of second charge sheet since the action of compulsory retirement was taken against the workman. Therefore the action taken against the workman imposing punishment of compulsory retirement is legal, proper and justified. The findings of the E.O. are on the basis of evidence placed before him and therefore the concerned workman is not entitled to any relief. The first party is thus sought the dismissal of the reference.

12. By filing rejoinder Ex.9, the concerned workman reiterated that the charges against him are not proved. Action of the management is illegal and therefore he is entitled for reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

13. Following issues are framed at Ex.8. Issue No.1 is treated as preliminary issue. Hence I reproduce the Issue No.1 along with my findings thereon for the reasons given below:

Sr. No.	Issue	Findings
1	Whether the enquiry by the management MbPT against workman Shri Jaywant Govind Raut, Mazdoor, Telephone Section, P&R Department, was fair and proper ?	Yes
2.	Whether the findings of the Enquiry Officer are perverse ?	Not perverse
3.	If yes, whether the punishment of compulsory retirement is adequate ?	Yes
4.	What relief the workman is entitled to ?	Not entitled to any relief
5.	What order ?	As per final order

14. On behalf of workman he examined himself to prove his case. In his examination i.e. evidence on affidavit he tried to prove all facts which he asserted in his statement of claim and re-joinder and on behalf of management, no witness is examined. My predecessor in Part – I awarded following points.

1. **Enquiry held is fair & proper.**
2. **Findings of the Enquiry Officer are not perverse.**
3. **Parties are directed to argue and lead evidence on the point of quantum of punishment.**

15. And he gave an opportunity to both the parties to lead any evidence on quantum of punishment but nobody filed any evidence but both the parties filed written notes of arguments. They also filed pursis to close the evidence on 8.3.17 and 7.6.17 (on behalf of management i.e. party No.1 his advocate closed his evidence on 7.6.17 and on behalf of worker i.e. party No.2 they closed evidence on 8.3.17).

16. After hearing of the argument my predecessor fixed this case on 24.2.20 for reserve of judgment.

17. Now I heard the arguments of both the parties today i.e. on 23.7.21, case fixed for award.

18. On behalf of workman, Party No.2 after relying case laws argued that

1. Learned Disciplinary Authority has not considered my unblemished record of service for 25 years and further by imposing the punishment of Compulsory retirement deprived me of my pensionary benefits.
2. I am not gainfully employed and have not obtained a job even though I have tried for the same considering my advanced age, as also the fact that I am not highly educated.
3. The findings is perverse.

19. On the basis of these arguments he prays that he must be reinstated with all consequence benefits and continuity of service with full back wages.

20. On behalf of management they relied on following case laws argued that;

1. The workman was given clear acquittal in Criminal case on the basis of alleged same facts. It is firstly respectfully submitted that the charges in the Criminal Trial and in the Disciplinary Proceedings cannot be held to be same if the Charge sheet dated 5th January 2007 at pages 5 to 10 of Exhibit 25.
2. Judgment and order of Criminal Court of acquitting the Second Party Workman would not automatically replace the Order of Compulsory retirement imposing punishment of Compulsory Retirement upon the Second Party workman.
3. Retirement benefits including pension during life and thereafter pension to the legal representatives is proper punishment and no interference is called for.
4. No interference is called for in the Order of Compulsory Retirement imposing punishment of Compulsory Retirement with retirement benefits.
5. Reference is rejected with cost in interest of justice.

21. Now I want to see legal position

Cases filed by Advocate of second party workman.

1. M/s. Glaxo Laboratores (I) Ltd. V/s. Presiding Officer, Labour Court, Meerut & Ors.—SCC—1994 –1 in which Hon'ble Supreme Court held that "substantial and proximate nexus between misconduct and employment essential – Place and time have a significant bearing in determining whether an act constituted misconduct – Certified standing order requiring the specified misconduct to be "committed within the premises of the establishment or in the vicinity thereof" – Interpretation of, in the context of the language used and its intendment."
2. Hardwari Lal V/s. State of UP & Ors. – SC – 2000 (2) – L.L.N. 69 in which Hon'ble Supreme Court held that "dismissal of appellant set aside on ground of violation of principles of natural justice – Reinstatement ordered – Considering the fact of long lapse of time between dismissal and reinstatement and no blame can be put on the door respondents, award of 50 per cent back-wages considered appropriate."

Cases filed by Advocate of First party.

1. State Bank of Patiala & Ors V/s. S.K. Sharma – SC – 1996 II CLR – 29 in which Hon'ble Supreme Court held that "principles of natural justice cannot be reduced to any hard and fast formulas. They cannot be put into a straight-jacket. Their applicability depends upon the context and facts and circumstances of each case. The objective is to ensure a fair hearing, a fair deal, to the person whose rights are affected."
2. M/s. Banaras Electric Light and Power Co. Ltd. V/s. The Labour Court II, Lucknow and Ors. – SC – 1972 – Page 328 – II – LLJ in which Hon'ble Supreme Court held that "the findings of the Labour Court and the High Court as to victimization are based on no evidence and are wholly unwarranted."

22. As I mentioned that workman examined himself but no witness is examined on behalf of management. Now I want to see evidence part of this case.

23. Workman Shri Jaywant Govind Raut, WW-1 in his cross examination admitted most of the facts. Now I want to mention here the part of the statement which is mentioned in para 17 & 18. He also admitted that "On each page of enquiry proceedings there are signatures of mine and my defence counsel. It is true that enquiry initiated against me on the basis of letter dt. 3.2.06 given by Sr. Inspector, MRA Marg Police station... It is true that I was given opportunity to file my documents during enquiry. It is true that during enquiry I have examined myself and my witnesses and management cross examined me and my witnesses..... I have also submitted my say before inquiry officer..... Thereafter I was given show cause notice calling upon me to give say on the inquiry officer report. It is true that during pendency of this inquiry I received another charge sheet. It is true that I have asked for translated copy of charge sheet in Marathi I have received the copy of the same in Marathi. It is true that papers of second charge sheet are included in the first charge sheet..... I was given punishment in respect of first charge sheet.

24. He also admitted that it is true that I preferred appeal before Dy. Chairman and as per order of Dy. Chairman my punishment of removal was modified to compulsory retirement.

25. On the perusal of record it appears that workman started his services on 16.11.1981 as Mazdoor. He asserted in his chief examination so many facts regarding assault and threat but this fact was not proved by court evidence. He also admitted that during the pendency of first enquiry he received another charge sheet. He also

admitted that second charge sheet are included in the first charge sheet but punishment given only for first charge sheet. He also admitted that disciplinary authority punished him "removal from services" which was modified to as "compulsory retirement". He also orally admitted in the court that he completed 15 years service.

26. On going through above discussion and considering with touch stone of case law in my humble opinion finding of criminal court is not binding with civil court. I also feel punishment as to 'compulsory retirement' is not punishment in civil conduct rules. Nothing show that finding of disciplinary authority with regard to punishment as well as modified view of appellate authority from "removal from services" to "compulsory retirement" is not appear to be shocking. It also appear that in comparing the misconduct of the workman, no employer is allow such type of worker in their establishment where male and female are working or public dealing. So in my humble opinion view taken by Appellate Authority is not illegal and unjustified.

27. Hence I pass the following order.

ORDER

1. **Action of management of Mumbai Port Trust by compulsory retiring the workman Shri Jayawant Govind Raut, Mazdoor, Telephone Section, P & R Department of the Mumbai Port Trust w.e.f. 19.3.2008 is legal & justified.**
2. **The workman is not entitled to any relief.**

SHYAM. S. GARG, Presiding Officer/Link Officer